he was first speaker to rise and say that because the reservations for Scheduled Castes and others are going to be made available, we are supporting the Bill. This is what he said. Kishan Reddy ji, please take note of this and find out the actual position. Is it due to administrative delay, or, they are waiting for the fresh Census? What is the reason?

श्री राजाराम: धन्यवाद, महोदय।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to provide relief to the unorganized sector adversely affected by the Covid-19 pandemic

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, this is regarding aid for informal sector workers, that is, daily wage labourers, artists, traders, weavers and craftspersons. Obviously, all of them have lots of problems after the pandemic. I have two points. Firstly, the 70-year old All-India Handicraft Board, based in Kolkata, has been abolished by the Centre. Sir, regarding the All-India Handloom and All-India Powerloom Board, my appeal is to re-open these Boards at the earliest. Sir, for transferring money to these unorganized sector workers -- be they artisans, be they artists, be they weavers -- in Bengal, there is a scheme called *Prochesta Scheme*, under which ₹ 1,000 are directly

[Shri Derek O' Brien]

transferred into the bank accounts. There was another one called 'Sneher Paras', which transferred ₹ 1,000 into the bank accounts.

Sir, day before yesterday was the beginning of auspicious Durga Puja, Mahalaya. But, a lot of these weavers, artists and labourers are going through a lot of problems, and, this is such an important festival, which will generate income for thousands of them. So, my appeal to the Centre is to use the Bengal model and to facilitate cash transfers to all these informal sector workers. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri Subhash Chandra Singh to associate. आपको क्या कहना है, वह आप एक वाक्य में कहें।

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, in the migration-prone Districts of Odisha, namely, Bolangir, Baragada and Nuapada, the State Government under the leadership of Shri Naveen Patnaik ji, had introduced 200-days work in a year for MNREGA workers, and, minimum wage of ₹ 300 per day was introduced with a special fund of ₹ 500 crore. Accordingly, in the Central Government, इस तरीके से, throughout the nation, under MNREGA, 200 working days होना चाहिए and Minimum Wage should be raised to ₹ 300 per day.

Secondly, Sir, already Unorganised Workers' Social Security Act जो बनाया गया है, इसी में, till today, how much money the Central Government has sanctioned. During this period, the Central Government should sanction some money. Thank you.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Concern over legal challenge to the Constitution (97th Amendment) Act, 2011 regarding Cooperative Societies

डा. चन्द्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, देश का सहकारी क्षेत्र ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में 40 करोड़ लोग सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं और आठ लाख सहकारी संस्थाएं हैं। चूंकि प्रदेश का विषय होने के कारण विभिन्न प्रदेशों के जो कानून हैं, वे अलग-अलग तरीके के बने हुए हैं। उन कानूनों में पारदर्शिता लाने के लिए, उन कानूनों में समानता लाने के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 97th Constitutional Amendment 2011 में लाया गया। माननीय सभापति जी, दोनों सदनों से यह सर्व-सम्मति से पास हुआ। इसका फरवरी, 2012 में नोटिफिकेशन हो गया और 16 राज्यों ने इस परिप्रेक्ष्य में अपने कानून में परिवर्तन भी कर लिया, लेकिन गुजरात के व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय में संसदीय प्रक्रिया में लैप्स होने के कारण उसमें स्थगन आदेश ले लिया।

सभापति महोदय, 10 वर्षों से यह Constitution Amendment pending है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूरे देश में इसके ऊपर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में सरकार प्रभावी कदम उठाए। माननीय उच्चतम न्यायालय में जो मुकदमा पेंडिंग है, उसकी प्रभावी पैरवी करके इस देश के 40 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

†**جاوید علی خان (اترپردیش):** مہودے، میں مانیئے سدسیئے کے ذریعہ اٹھائے گئے موضوع سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

†Transliteration in Urdu script.